International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(II), January - March, 2023, pp. 119-122

मौद्रिक नीति और महंगाई

डॉ. जगदीश प्रसाद मीना*

सार

कोरोना महामारी से उतर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को जिस तरह अचानक यूक्रेन संकट का सामना करना पड़ा, उसके नतीजे में महंगाई बढ़नी ही थी, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी जूझ रहा है। भारत तो एक ऐसा देश है, जो अपनी जरूरत का 80 फीसदी से अधिक कच्चा तेल आयात करता इस वजह से भारत पर कही अधिक प्रभाव पड़ता है और उसका असर आज देख रहे हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद के प्रतिदिन पिछले दस से अधिक दिनो से पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने का सिलसिला बना हुआ है। फिलहाल यह कह पाना कठिन है कि आखिर यह सिलसिला कब बंद होगा, लेकिन यदि यह बढ़ोत्तरी नहीं रूकी तो महॅगाई की चुनौती और गंभीर होना तय है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। यदि उसकी अनदेखी की जाती है तो हमारे हालात पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे होने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन संकट तो पिछले चालीस दिनों से बना हुआ है, लेकिन महंगाई तो इससे काफी पहले से ही चल रहीं है। रोजमर्रा के काम में आने वाली कोई ऐसी चीज नहीं बची है, जो महंगी नहीं हो। धनाढ्य वर्ग को छोड़कर आज हर वर्ग का जीना मुश्किल बना हुआ है। घरेलू गैस का सिलेंडर एक हजार रूपये से पार पहुँच गया है। कारोबारी सिलेंडर की कीमत पिछले एक महीने में ही दो बार बढ़ गई है। ताजा बढ़ोतरी सौ रूपये तक हुई है। इसी तरह पाइप लाइन के जरिये सप्लाई की जाने वाली रसोई गैस की कीमत पांच रूपए प्रति घनमीटर बढ़ा दी गई है। खुदरा और थोक महंगाई का समय अपने शिखर पर है, इस बीच पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ रही कीमतों से महंगाई और बढ़ेगी। माल–ढुलाई का खर्च बढ़ने से उसकी मार हर वस्तु और हर वर्ग पर पड़ेगी। इस समय तेल पर करीब 27 रुपए प्रतिलीटर उत्पाद शुल्क वसुला जाता है। अगर सरकार केवल उसमे कटौती कर दे तो कीमतें नियन्त्रण में आ जाएगी। मगर सरकार का इरादा शायद ऐसा करना नहीं है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भले ही यूक्रेन युद्ध दुनिया के एक कोने में लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसका असर सभी देशों पर कुछ इस तरह पड़ रहा है जैसा कोरोना महामारी के दौरान पड़ा था। वित्तमंत्री की बात सही हो सकती है, लेकिन समस्याओं का उल्लेख करने मात्र में हल होने वाला नहीं हैं। सरकार को कुछ ऐसे कदम बढ़ाने को आगे को आगे आना चाहिए, जिससे यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों के प्रभाव कुछ कम किया जा सके।

शब्दकोशः *वैश्विक, मौद्रिक नीति, मूल्यवृद्धि, थोक महंगाई, लोन टू वैल्यू।*

प्रस्तावना

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाली समिति ने इस बार जो फैसले लिए हैं, उससे इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि बैंक का अर्थव्यवस्था की जगह ज्यादा ध्यान महंगाई पर केन्द्रित हो गया हैं। बैंक ने नई रणनीति के तहत धीरे–धीरे बैंकिंग सिस्टम में नगदी सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करेगी, ताकि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। बैंक की नीति में बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी देश के बैंकिंग सिस्टम में करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नगदी है। कोविड महामारी के दौरान पाबंदियों के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सिस्टम में नगदी बढ़ाई गई थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से मंहगाई बैंक की सहूलियत वाली स्थिति 4 फीसदी से उपर, निकल गई है। बैंकिंग सिस्टम में जब नगदी

* सहायक आचार्य – ई. ए. एफ. एम., स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

ज्यादा हो तो महंगाई में मदद मिलती है मगर आरबीआई ने महंगाई काफी बढ़ने के बावजूद रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट के साथ एलटीवी आनी लोन टू–वेल्यू में बदलाव नहीं किया है। इसमे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उद्योग जगत को भी लाभ मिलेगा। कम ब्याज पर अधिकतम लोन मिलने से व्यापार मे अनिश्चितता बनी रहेगी। उद्योगों की लागत बढ़ी है, लेकिन ब्याज नही बढ़ना अच्छा संकेत है लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने यह भी संकेत दिया है कि नीतिगत दरों में बदलाव न करने की स्थिति ज्यादा नहीं चल सकती। लगता है कि समिति आने वाले दिनों के जोखिमों को समझ रही है। इसलिए उसने मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.7 फीसदी कर दिया है, जबकि इस साल फरवरी में यह साढ़े चार फीसदी रखा गया था। इसके अलावा हालात को देखते जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान भी घटा कर 7.2 फीसद कर दिया है, जो पहले 7.8 फीसदी था महंगाई और ग्रोथ के अनुमानों में बदलाव इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और बढ़ सकती है। जहां तक महंगाई का सवाल है तो शीर्ष बैंक यह पहले से ही कर रहा है कि इस साल यानी 2022–23 में भी महंगाई से मुक्ति नही मिलने वाली है। शीर्ष बैंक का अनुमान सही भी है, क्योंकि जिस तरह से डीजल–पेट्रोल से लेकर रसोई गैस और सीएनजी व पीएनजी के दाम जिस गति से बढ़ रहे है, उससे महंगाई बेलगाम हो गई है। आम आदमी व मध्यम वर्ग महंगाई से काफी त्रस्त है। रिजर्व बैंक हालात से अच्छी तरह वाकिफ है और कुछ नए कदम भी उठा रहा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय मुश्किलों व चुनौतियों से ही भरा है।

मौद्रिक नीति द्वारा महंगाई पर नियंत्रण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के अन्तर्गत कोई भी नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है तथा यथास्थिति वादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कोरोना काल में घोषित नीति को ही लागू किया गया है। सम्भावना व्यक्त की जा रही थी कि विश्व के विकसित देशों में मूल्य वृद्धि जनित मुद्रास्फीतिब्याज दरों पर प्रभाव पड़ा है तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दर में वृद्धि का नीतिगत निर्णय हो सकता है इम सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का मानना है कि विश्व के दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारत में मूल्य वृद्धि के प्रभाव एवं कारणों में अंतर है। भारत में मूल्य वृद्धि के कारण विकसित देशों की तुलना में अलग है। विश्व के देशों में विश्व खाद्य संगठन के अनुसार खाद्य मूल्य वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत है, जबकि भारत में खाद्य मूल्य वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत है, जबकि भारत में खाद्य मूल्य वृद्धि 6.5 प्रतिशत है। अमेरिका में कार मूल्य वृद्धि का कारण है लेकिन भारत में नहीं है। यूरोपीय देशों में ट्रकों को चलाने के लिए ड्राइवर की उपलब्धता मूल्य वृद्धि की सम्भावनाओं एवं जोखिम का विशेषण करके एवं आमिकान जैसे कोरोना के पड़ने प्रभावों को ध्यान में रखते ही यथावत एवं समायोजित मौद्रिक नीति घोषित की गई है तथा मौद्रिक नीति समिति की भी यही सिफारिश है।

मौद्रिक नीति के अन्तर्गत विकास एवं मूल्य स्थिरता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के लिए 8 मे 8.5 प्रतिशत आर्थिक विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास दर वृद्धि का अनुमान 7.8 प्रतिशत लगाया है इसी तरह से खुदरा मद्रा प्रसार 5.3 प्रतिशत घटकर वर्ष 2013 में 4.5 प्रतिशत रह जाएगा वर्तमान खुदरा मुद्रा मूल्य सूचकांक लगभग 6 प्रतिशत है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक 12 से 13 प्रतिशत तक है। खुदरा मूल्य एवं थोक मूल्य सूचकांक में अन्तर का कारण कर माना जाता है जिसको कि खुदरा मूल्य सूचकांक की गणना में सम्मिलित नही किया जाता है। मौद्रिक नीति प्रतिवेदन में विकास दर में कमी का अनुमान है, लेकिन गुद्रास्फीति नियंत्रित सीमा में 4 से 6 प्रतिशत के मध्य रहेगी। देश में विकास दर में वृद्धि भी आवश्यक है तथा महंगाई पर नियन्त्रण भी देश के गरीब, निर्धन एक आमजन को विकास भी प्रभावित करता है तथा महंगाई भी। यदि विकास दर बढ़ती है तो रोजगार, आय एवं उत्पादन स्तर बढ़ता है, लेकिन महंगाई बढ़ती है तो आमजन का जेब खर्च बढ़ता है। लेकिन मूल्य वृद्धि का लाभ पूँजीपतियों व्यापारियों, दलालों एवं कम्पनियों की जेबों में तो जाता है, लेकिन गरीब की जेब तो खाली हो जाती है। इसका सीधा सा कारण भारत में मजदूरी की दरें तेजी से नही बढ़ती है तथा न्यूनतम मजदूरी अधनियम सरकारी एवं संगठित क्षेत्रों पर तो लागू होता है लेकिन असंगठिन एवं निजी क्षेत्र पर नही।

ताजा रिपोर्ट है कि थोक महंगाई कुछ कम हो गई। पिछले 22 महिनों में सबसे कम। हम आम लोग ऐसी रिपोर्ट देखकर चौकते हैं। सोचते है खर्चा तो कम होता नहीं, महंगाई किधर से और कैसे कम हो जाती है, समझ में नहीं आता। दरअसल हम अब महंगे–सस्ते की मनसिकता से लेकर बाजार जाते ही नहीं। हमारी दिनचर्या ही ऐसी हो गई है कि महंगाई के मायने बेमतलब हो गए है किसी चीज का भाव पूछना हमारी आदत नहीं रही। किराना हो, कपड़ा हो या और कोई महंगी चीज, हम बास्केट में रखते है और इक्ट्ठा बिल चुकाते हैं। महंगे सस्ते का अंदाजा होगा कैसे? फिर पैसे भी हाथ से गिनकर देने के तो जमाने लद गए। कार्ड से पेमेंट करते हैं। पता ही नहीं चलता कितना महंगा पड़ा। एक जमाना था जब कपड़े का भी भाव होता था । लोग मीटर से लेते थे और दर्जी से सिलवाते थे। महंगे और सस्ते कपडे का अन्दाजा रहता था। जितने पैसे लेकर घर से निकलते थे, लोटते वक्त जेब खाली, ठन ठन गोपाल हो जाते थे। तो पता चलता था, महंगाई कितनी बढ़ गई है, अब तो हम ब्रांड देखकर शोप जाते हैं और जो शर्ट या पैंट पसंद आए उसे पहनकर देखते है। नाप ठीक होना चाहिए। कीमत पर ध्यान नहीं देते। महॅगाई कितनी है, पता ही नहीं चलता।

दूसरी तरफ देश में कई लोग ऐसे हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है। पहनने को कपड़े नहीं है। दो वक्त की रोटी भी मुश्किल है। उन्हें महंगे – सस्ते का अन्दाजा है और हर वक्त होता भी है लेकिन उसकी आवाज सुनता कौन है। उनके भाव और भावनाओं से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। यही वजह है कि देश में अब क्या महंगा और सस्ता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम महंगाई से अंदाज केवल इसी से लगाते हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव कितने बढ़ गए हैं। चूँकी माल–दुलाई में सबसे बड़ा सेग्मेंट पेट्रोल–डीजल ही होता है, इसलिए महंगाई पर इसका फर्क भी होता है लेकिन भाव जो भी हो जाए, हम पेट्रोल डीजल के महंगे होने से घूमना–फिरना तो बन्द करते नहीं है और जो साइकिल पर हैं या पैदल हैं, उन्हें इससे कोई वास्ता नहीं है। दरअसल, हमारा जीवन चक्र ही ऐसा हो गया है कि मंहगे–सस्ते जैसे शब्द अब बेमानी हो चले हैं। यही वजह है कि वर्षो से महंगाई के खिलाफ देश में कोई बड़ा अन्दोलन नहीं हुआ। हुआ भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जमाना लद चुका है जब प्याज की महंगाई सरकारें गिरा दिया करती थी। देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है पेट्रोल–डीजल से लेकर फल और सब्जियों के दाम आसमान पर है। खाने वाले तेल की कीमत भी लगातार बढ़ने से किचन के बजट पर काफी असर पड़ा है। हालांकि सरसों के तेल में काफी कमी देखी गई है। रसोई गैस की कीमतें भी काफी बढ़ गई है जिससे गैस सिलेंडर खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। गेहूँ, चावल, आटा, दाल और तेल के दाम में पिछले महीने की तुलना में ही काफी इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में पिछले एक महीने की तुलना में कुल 10 फिसदी का इजाफा देखा गया है।

महंगाई का प्रभाव

महंगाई को रोकने एवं विकास दर से वृद्धि का उपाय यह है कि ब्याज दरें संतुलित एवं स्थिर रहे। मौद्रिक नीति में उल्लेखित बैंक दर, रेपो दर एवं रिजर्व रेपो दर साख की लागत को प्रभावित करती है तथा बचत पर मिलने वाले ब्याज दर से भी इसका सम्बन्ध है। यदि उपभोग को बढ़ाना है तो ब्याज दर कम होनी चाहिए ताकि मांग में उठाव पैदा हो। मांग का उपभोग स्तर पूर्व कोरोना काल के स्तर पर आए। देश में रियलिटी एवं निर्माण क्षेत्र, होटल एवं पर्यटन व्यवसाय, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इलेक्ट्रोनिक उत्पाद आदि कोराना से सर्वाधिक प्रभावित हुए है। इन उत्पादों में लगी कम्पनियों एवं थोक व खुदरा व्यापारियों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। यदि ब्याज दरें बढ़ती है तो उपभोक्ता ऋण महंगे हो जाते है तथा बड़ी लागत को उपभोक्ता तक लादने में उत्पादक व व्यापारी 'शत–प्रतिशत सफल नहीं हो पाते है। उपभोक्ता वस्तुओं में हुई मूल्य वृद्धि में कर नीति एवं साख की लागत का अत्यधिक प्रभाव होता है, जो कि आपूर्ति बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे मे साख ही उठाव क्षमता को बनाए रखना एवं बढ़ाना है। देश के मांग के साथ–साथ पूर्ति बाधाएँ भी मूल्य वृद्धि का कारण बन जाती है जो कि लॉजिस्टिक लागत को बढ़ाती है। देश में लॉजिस्टिक लागत अत्यधिक है, जो कि 15 से 20 प्रतिशत तक है, जबकि चीन में मात्र ऐसे 5 प्रतिशत है। यह भी कारण है कि दुनिया के देशों में चीन सस्ता उत्पाद बेचने मे सफल हो जाता है। देश में आगामी समय में सम्भावित सामान्य मानसून, निर्यात बढोतरी, नए बजट में पूँजीगत व्यय में वृद्धि तथा इंफ्रास्टकर प्राथमिकता वृद्धि की दृष्टि से मूल्य राहत प्रदान होने की सम्भावनाएं हैं, लेकिन देश में खाद्य

एवं ऊर्जा मूल्य वृद्धि पर कोई नियन्त्रण नहीं है। खाद्य उत्पादों के मुख्य तेजी से बढ़ते है तो मूल्य सूचकांक भी बढ़ता है जिसके लिए आयात एक विकल्प है। देश में दालों एवं खाद्य तेल के सम्बन्ध में यह बात लागू होती है।, दूसरी समस्या खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में तेजी से वृद्धि है, जो कि दिसम्बर 2021 से 69 डालर प्रति बैरल था जो कि अभी 94 प्रति बैरल हो गया है तथा रूस यूक्रेन के युद्ध एवं रूस व अमेरिकी देशों की खनिज तेल उत्पादन की भावी नीति मूल्य वृद्धि का कारण बनने की सम्भावना है

भारत में खुदरा महंगाई दर 6.1 फीसदी पर पहुँच गई है। यह पिछले छह माह में सबसे ज्यादा है। दिसम्बर 2021 में महंगाई दर 5.66 फीसदी थी। हालांकि जनवरी में थोक महंगाई दर में मामूली गिरावट भी दर्ज हुई है। यह 12.96 फीसदी तक है जबकि दिसम्बर 21 में यह आंकडा 13.56 फीसदी पर था । चिन्ता की बात यह है कि जनवरी में दर्ज महंगाई का आंकड़ा ज्यादा चिन्ताजनक इसलिए है कि यह रिजर्व बैंक निर्धारित दो से छह फीसदी के दायरें में होती है तो यह बैंक के लिए कोई समस्या नहीं होती। अब जब महंगाई दर दायरे से बाहर है तो महंगाई बड़ा संकट बन जाती है। हालांकि रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी नीतिगत दरों को पेश करते समय साफ ईशारा किया था कि मार्च से सितम्बर तक महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। साथ ही बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। नीतिगत दरें बढ़ाने का असर महंगाई बढ़ने पर और पडता। सरकार के ताजा आंकडे बताते हैं कि खाद्यमुद्रा– स्फीति बढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़ी है। खाने–पीने की सभी वस्तुओं के दाम काफी बढ़ें हुए हैं। जनवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 10.33 फीसदी पर पहुँच गई है, जो आम आदमी पर काफी बोझ डालने वाली है। आज दाले, धान, खाद्य तेल आदि सभी काफी बोझ डालने वाली है। आज दाल, धान, खाद्य तेल आदि सभी काफी महंगे मिल रहे। जनवरी से सब्जियों व फलों के दामों में भी उछाल देखा गया। सवाल है कि अगर खाने–पीने के वस्तुएँ उसी तरह महंगी होती रही तो आम आदमी का गुजारा कैसा हो सकेगा। यह सब उस हालत में हो रहा है, जब देश में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बडा संकट बना हुआ है। केन्द्र से लेकर राज्य सरकारे बेशक यह दावा करती रही हैं कि लोगों को दो पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाया जाता लेकिन हकीकत से सभी वाकिफ है। बेरोजगारी की वजह से महंगाई की मार ज्यादा पड़ रही है। रसोई गैस सिलेण्डरों के दाम से लेकर पेट्रोल–डीजल तक लम्बे समय से महंगे बने हुए हैं।

निष्कर्ष

महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्र नीति बनाने की जरूरत है जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से महंगाई को रोक पाना बहुत जरूरी है नहीं तो हमारी स्वतंत्रता को वापिस खतरा उत्पन्न हो जायेगा। हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण देश में बढ़ती जनसंख्या है। जब तक हम जनसंख्या को नियन्त्रण नहीं करेंगे महंगाई को रोकना मुश्किल है। महंगाई की वजह से निम्न वर्ग के लोगों को जरूरत की चीजें नहीं मिल पाती है और इसमें अपने रोजमर्रा जीवन में खुशी सें जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। महंगाई ने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था इससे आम आदमी की खरीदने की शक्ति को कम कर दिया है। निवेश पर मिलने वाला रिर्टन महंगाई की दर के साथ ताल मेल नहीं बिढा पा रहा है। छोटी बचत योजनाओं को इतना रिर्टन देने की क्षमता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में छोटी बचत योजना की ब्याज दरों में कमी आई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत में आर्थिक पर्यावरण – शर्मा, वशिष्ठ, अग्रवाल
2. भारतीय अर्थव्यवस्था –शर्मा, जैन
3. भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था–लेखक–गुप्ता, वशिष्ठ, शर्मा, रमेश बुक डिपो जयपुर
4. बैकिंग एवं वित्त लेखक डी. आर. जाट, तिवारी अजमेरा बुक कम्पनी जयपुर
5. प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक :– भारतीय अर्थव्यस्था
6. न्यूज पेपर, Times of India
7. दैनिक नवज्योति 12 अप्रैल 2022
8. दैनिक भास्कर 18 जनवरी 2023
9. योजना, इण्डिया टुडे, नेट, विकीपीडिया।

❖◆❖